



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 69 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2001/फाल्गुन 22, 1922

No. 69]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2001/PHALGUNA 22, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

प्रारम्भिक निष्कर्ष

विषय : पोलैंड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाईस्टाइरिन बुटाडिन कोपोलीमर/हाईस्टाइरिन रेजिन/रबड़ ( एचएसआर ) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 22/1/2000-डीजीएडी. — वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. कार्यपद्धति

जांच के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई गई है:

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) को उपरोक्त नियमावली के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 और मै0 एपकोटैक्स लैट्टीसीज लि0 (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता कहा जाएगा) जिनके पंजीकृत कार्यालय क्रमशः अपार हाऊस, कारपोरेट पार्क, सियोन-ट्राम्बे रोड, चम्बूर, मुम्बई-400021 तथा 49-53, महावीर सेंटर, प्लॉट नं. 77, सैक्टर-17, वशी, नवी मुम्बई-400073 हैं, जिसमें पोलैंड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र ( इसके बाद इन्हे सम्बद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई स्टाइरिन बुटाडिन कोपोलीमर/हाईस्टाइरिन रेजिन/रबड़ (एचएसआर) (इसके बाद सम्बद्ध वस्तुएं कहा जाएगा) के पाटन का आरोप लगाया गया है।

- (ii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका की आरंभिक जांच से कतिपय त्रुटियों का पता लगा जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा बाद में ठीक कर दिया गया । इसके बाद याचिका को सही ढंग से प्रलेखित दस्तावेज माना गया है ।
- (iii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी ने पोलैंड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध जांच आरंभ करने का निर्णय लिया है । प्राधिकारी ने उपनियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले पाटन के आरोप प्राप्त होने के बारे में नई दिल्ली स्थित पोलैंड के दूतावास तथा नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधिमंडल (इसके बाद सम्बद्ध देशों के दूतावास कहा जाएगा ) को सूचित किया ।
- (iv) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची के सीमाशुल्क कोड 4002.1902 के अंतर्गत वर्गीकृत पोलैंड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के सम्बद्ध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए दिनांक 20.12.2000 की सार्वजनिक सूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की ।
- (v) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्योरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे ) तथा उद्योग संघों को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया ।
- (vi) प्राधिकारी ने भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों (जिनका विवरण याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में देने का अनुरोध किया ।

- (vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से जांच अवधि सहित पिछले 3 वर्षों में भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों का विवरण देने का अनुरोध किया गया था ।
- (viii) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देशों के दूतावासों को भेजी । याचिका की एक प्रति अन्य हितबद्ध पार्टियों को भी अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई ।
- (ix) प्राधिकारी ने सम्बद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी:
1. मै0 बॉयर एजी, जर्मनी
  2. मै0 एनीकैम इलास्टोमेरी एसआरएल, इटली
  3. मै0 हुल्स एजी, जर्मनी
  4. मै0 बुनावर्क हुल्स गम्भ, जर्मनी
  5. मै0 कैमिकल कम्पनी "उवोरी" एसए, पोलैंड
- (x) नई दिल्ली में सम्बद्ध देशों के दूतावासों को भी नियम 6(2) के अनुसार जांच आरंभ होने की सूचना दे दी गयी थी और उसने अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भरकर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था । निर्यातको को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावास को भी भेजी गई थी ।
- (xi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए सम्बद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोक्ता संघों को प्रश्नावली भेजी गई थी:-
1. मै0 बानिक रबड़, कलकत्ता
  2. मै0 बी. रबड़, गाजियाबाद
  3. मै0 ओसवाल इंडस्ट्रीज, दिल्ली
  4. मै0 लखानी, हरियाणा

5. मै0 अस्थी एंटर प्राइज, नौएडा

(xii) सम्बद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना दी गई:

1. मै0 फर्मा कैमिकजना डवोरी एसए, पोलैंड, मैसर्स आर्थर एंडरसन द्वारा दायर की गई ।

2. मै0 बायर इंटरनेशन एसए, स्विटजरलैंड

(xiii) निम्नलिखित आयातकों/उपयोक्ता संघों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना प्रस्तुत की गई ।

1. मै0 पैरागोन रबड़, इंडस्ट्रीज, केरल स्ट्रेटजिक लॉ ग्रुप द्वारा

2. मै0 लियो रबर्स, केरल उत्तर दिया गया

3. मै0 पैरागोन पोलीमर्स, केरल

4. मै0 मलाया ट्रेड इम्पैक्स प्रा. लि., कोट्टायम (मै0 शर्मा एसोसिएट्स द्वारा उत्तर दिया गया)

5. मै0 आल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुट वियर मैन्यूफैक्चरर्स, नई दिल्ली

6. ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

7. ऑफ इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मुम्बई

मै0 ऋषिरूप पोलीमर्स प्रा0 लि0, मुम्बई ने हितबद्ध पक्ष के रूप में उत्तर दिया न कि आयातक/निर्यातक के रूप में ।

(xiv) उत्पादन की लागत सहित विभिन्न क्षति संबंधी परिमाणों के बारे में अतिरिक्त सूचना याचिकाकर्ताओं से मांगी गई थी जो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी ।

(xv) प्राधिकारी ने, जितना आवश्यक था, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की ।

- (xvi) प्राधिकारी ने अपने पास सार्वजनिक फाइल के रूप में रखी गई सूचना और साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को हितबद्ध पार्टियों द्वारा देखने के लिए खुला रखा ।
- (xvii) सामान्यतः या स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के विश्लेषण के आधार पर भारत में विषयगत माल की इष्टतम उत्पादन लागत तथा माल को बनाने और बेचने की न्यूनतम लागत का हिसाब लगाया गया ।
- (xviii)\*\*\* चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का घोटक है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है ।
- (xix) यह जांच 1.1.2000 से 30.9.2000 अर्थात् जांच अवधि से शुरू होने वाली अवधि के लिए की गई थी ।
- (xx) निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार ।

#### याचिकाकर्ताओं के विचार:

##### क. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के संबंध में

- (i) इस उत्पाद का पूर्ण विवरण हाई स्टाइरीन बुटाडीन कोपोलीमर है और इसे हाई स्टाइरीन रेजिन/रबड़ (एचएसआर) भी कहा जाता है जिसमें एसबीआर 1900 श्रेणी एवं एचएसबीआर भी शामिल है । एसबीआर 1900 श्रेणी का उल्लेख हाई स्टाइरीन रेजिन के मास्टर बैच (जिसे इमलशन रेजिन रबड़ मास्टर बैच भी कहा जाता है) के लिए किया जाता है । एचएसआरबी का उल्लेख हाई स्टाइरीन रिइन्फोर्समेंट पोलिमर्स के लिए होता है ।
- (ii) एचएसआर विभिन्न ग्रेडों और किस्मों का ही हो सकता है और इस दानेदार एवं गट्ठे के रूप में उत्पादित किया जाता है । एचएसआर श्रेणी का सामान्यतः स्टाइरीन घटक

एवं चन्द्राकार विस्कोसिटी के रूप में उल्लेख किया जाता है । भारतीय उद्योग ऐसे एचएसआर का उत्पादन करता है जो उन सभी श्रेणियों के समान है जिनका वर्तमान में पोलैंड और यूरोपीय संघ से भारत में आयात किया जा रहा है । इसके अलावा उद्योग उन सभी श्रेणियों के समान उत्पादन करने की स्थिति में है जिनका पोलैंड तथा यूरोपीय संघ में उत्पादन किया जा रहा है भले ही इनका वर्तमान में भारत को निर्यात नहीं किया जा रहा है ।

- (iii) एचएसआर का विनिर्माण केवल स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबड़ के उत्पादकों द्वारा किया जाता है और इसका रबड़ उद्योग में उपयोग किया जाता है ।
- (iv) एचएसआर को सीमाशुल्क उपशीर्ष 4002.1902 के अंतर्गत अध्याय 40 में वर्गीकृत किया गया है और इसका सीमाशुल्क उपशीर्ष 3903.9000 के अंतर्गत भी आयात किया जाता है । अध्याय 39 तथा 40 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के बीच एकमात्र अंतर स्टाइरीन के प्रतिशत घटक का है जो उत्पाद को भिन्न उत्पाद नहीं बनाता है और इस उत्पाद के लगभग एक समान तकनीकी एवं वाणिज्यिक उपयोग होते हैं ।
- (v) विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित एचएसआर के इस्तेमाल का सामंजस्य बैठाने के लिए एचएसआर के इस्तेमाल में उत्पादन प्रक्रिया की फाइन ट्यूनिंग करने की आवश्यकता होती है । भारत तथा विश्व के अन्य भागों में उपभोक्त किसी भी विनिर्माता द्वारा उत्पादित एचएसआर को संयंत्र एवं उपकरण में कोई परिवर्तन किए बगैर अदल-बदल कर इस्तेमाल कर सकता है ।
- (vi) एचएसआर का कोई सीधा प्रतिस्थापक नहीं है । फुटवियर उपयोग में इस्तेमाल करने वाले ईवीए आदि जैसे अन्य पोलिमेर्स हैं । तथापि, ईवीए एचएसआर को सीधे रूप से प्रतिस्थापित नहीं करता है ।
- (vii) याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एचएसआर और संबद्ध देशों से निर्यातित एचएसआर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 तथा मै0 एपकोटेक्स लैटिसिस लि0 तथा पोलैंड एवं यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि विश्व भर में एचएसआर का उत्पादन पोलिमेराइजेशन प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है । तथापि, प्रत्येक उत्पादक उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अपनी उत्पादन प्रक्रिया की फाइन ट्यूनिंग करता है ।

**(ख) पाटन के संबंध में**

- (i) घरेलू उद्योग ने प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के आधार पर संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का आकलन किया है ।
- (ii) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन तथा पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों पर समायोजनों के साथ द्वितीयक स्रोत के आधार पर निर्यात कीमत उपलब्ध करवाई है ।
- (iii) यूरोपीय संघ के लिए पाटन मार्जिन 140% पर बताया गया है, जबकि पोलैंड के निर्यातकों के लिए यह 126% पर बताया गया है ।

**(ग) क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में**

घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि कई मापदण्डों से क्षति का पता चलता है:-

- (i) एक बहुत ही छोटी अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो भविष्य में अत्यधिक बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती है ।
- (ii) संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास निर्यात हेतु उपलब्ध पर्याप्त क्षमता है, यह देखते हुए कि हाल ही में अन्य देशों (जो अब तक सामग्री का निर्यात कर रहे थे) को इन देशों में पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत प्रभावी रूप से कवर किया गया है ।
- (iii) मुक्त रूप से पर्याप्त निपटान की क्षमता विद्यमान है यह देखते हुए कि विश्वभर में खपत निर्मित क्षमताओं से कहीं कम है और अन्य देशों पर शुल्क लगाए जाने पर इन देशों के निर्यातकों ने बाजार पर बहुत तेजी से कब्जा करने के प्रयास किए हैं ।
- (iv) भारत में ऐसी कीमतों पर आयात हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर अत्यधिक निराशाजनक प्रभाव पड़ा है और पड़ता रहेगा ।
- (v) ऐसी कीमतों पर आयात हो रहे हैं जो उन कीमतों से काफी कम हैं जिन पर भारतीय उत्पादकों द्वारा वस्तुओं की बिक्री की जा रही है । अतः आयातों से कीमतों में बेतहाशा कटौती हो रही है और इनसे आयातों में अत्यधिक वृद्धि अथवा घरेलू कीमतों में गिरावट आएगी ।

- (vi) घरेलू उद्योग के घाटे बहुत बढ़ गए हैं। उद्योग को उत्पादन की इष्टतम लागत तथा निवेशों पर समुचित वसूली से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- (vii) कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग के प्रचालन मार्जिन में अत्यधिक कमी आई है।
- (viii) घरेलू उद्योग के पास स्टॉक कॉफी बढ़ गए हैं।
- (ix) उद्योग का क्षमता उपयोग इष्टतम से कम रह गया है। उद्योग अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद अपने संयंत्र का अभीष्ट उपयोग नहीं कर पाया है।
- (x) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट गया है और इन देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हो रही है।
- (xi) घरेलू उद्योग के कर्मचारी पूरी तरह से हतोत्साहित हैं और बाजार में उत्पाद के जारी पाटन के परिणामस्वरूप वे उद्योग को छोड़ रहे हैं।
- (xii) इन हालातों में कार्यचालन को जारी रखना अलाभकारी हो गया है।
- (xiii) शेयर धारियों द्वारा कोई निवेश न किए जाने तथा आन्तरिक निधियों के बिना भारतीय बाजार में इस उत्पाद के जारी पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पनप पाने में सफल नहीं हैं।
- (xiv) एक विनिर्माता (सिंथेटिक एंड कैमिकल्स लि.) ने बीआईएफआर के पास पहले ही आवेदन कर दिया है।

## 2. निर्यातकों के विचार

(क) मै0 फर्मा कैमिकजना डौरी एस.ए. पोलैंड द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- (i) निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए यथानिर्धारित प्रश्नावली में घरेलू बिक्री कीमत, निर्यात कीमत तथा उन पर विभिन्न समायोजनों के ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं।
- (ii) निर्यातक ने भारत में अपने एजेंट को दी गई छूटों/कमीशनों, स्वदेशी भाड़े, विदेशी भाड़े, पैकिंग तथा वीएटी वापसी के लिए निर्यात बिक्रियों में समायोजन की मांग की है। निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत भी उपलब्ध करवाई है।



- (iii) निर्यातक ने कहा है कि उनके ऑकड़ों के अनुसार भारत को किए गए निर्यात के लिए कोई डम्पिंग मार्जिन नहीं है ।

**(ख) मै0 बेयर इंटरनेशनल एस.ए. स्विटजरलैंड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-**

- (i) निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि उन पर एसबीआर के संबंध में पहले ही पाटनरोधी जांच की गई है और उन्हें इससे दोषमुक्त किया गया है और उन्हें आश्चर्य हुआ है कि एक बार फिर एसबीआर की एक विशेष श्रेणी पर इसी प्रकार की जांच शुरू की गई है ।
- (ii) निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों के एक बीजक की प्रति, श्रीलंका को किए गए निर्यात के एक बीजक की प्रति तथा भारत को किए गए निर्यात के कुछ बीजकों की प्रतियाँ उपलब्ध करवाई हैं ।
- (iii) निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उन्होंने 437 टन एचएस 260 श्रेणी के क्राइलीन का निर्यात किया है और यह वर्ष 2000 के लिए कुल खपत का केवल 2% बनता है । याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि यह मात्रा स्वदेशी उत्पादकों को क्षति पहुँचाने के लिए काफी नहीं है ।

**3. आयातकों एवं प्रयोक्ता परिसंघों के विचार**

- (क) मै0 पैरागन रबड़ इंडस्ट्रीज, मै0 लिओ रबर्स एवं मै0 पैरागन पोलीमर्स द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-
- (i) जांच अवधि में उनके द्वारा संबद्ध वस्तुओं के जापान तथा यूएसए से किए गए आयातों के ब्यौरे उपलब्ध करवाए गए हैं और यह इंगित किया गया है कि पोलैंड से आयात केवल हाल ही में किए गए थे ।
- (ii) यह उल्लेख किया गया है कि वे रबड़ हवाई स्लीपरों का विनिर्माण करते हैं जो कि कम कीमत के कारण निम्न मध्य वर्ग तथा ग्रामीण लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य फुटवियर है और यह कि एचएसआर अच्छी गुणवत्ता वाली हवाई चप्पल का उत्पादन करने में मुख्य घटक है । सिंथेटिक रबड़ की लागत में कोई भी वृद्धि होने से उनकी उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ेगा और घरेलू उत्पादकों के उत्पाद गुणवत्ता में बहुत घटिया हैं और उनकी उत्पादन क्षमता भी कम है जबकि भारतीय फुटवियर उद्योग के लिए एचएसआर की वर्तमान मांग अब भी 30,000 मी. टन प्रति वर्ष से अधिक है ।

- (iii) आयातकों ने जांच अवधि में उनके द्वारा संबद्ध वस्तुओं के जापान तथा यूएसए से किए गए आयातों के ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं और उन्होंने उल्लेख किया है कि वे पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करते हुए उच्च लागत पर जापान से आयात कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि घरेलू विनिर्माताओं की गुणवत्ता घटिया है और यह आपूर्ति तथा गुणवत्ता दोनों के रूप में उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है। उन्होंने अब पोलैंड से आयात करना भी शुरू कर दिया है।
- (iv) पाटनरोधी शुल्क लगाने से लघु क्षेत्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे भारत में आम आदमी के बोझ में वृद्धि होगी।

(ख) मै0 मालाया ट्रेड इम्पैक्स प्रा. लि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i) उन्होंने जांच अवधि के दौरान पोलैंड से संबद्ध वस्तुओं अर्थात् के ई आर एच एस आर 1904 ग्रेड के आयातों का ब्यौरा समर्थनकारी बीजकों के साथ प्रस्तुत किया है। आयातक ने अन्य देशों से भी आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।

(क) मै. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:-

- i) एच एस आर का उपयोग टायर उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और यह कि उसका मानना है कि दोनों ग्रेडों अर्थात् एस बी आर 1702 और 1502 जोकि टायर उद्योग द्वारा खपत किए जाते हैं को भी जांच के दायरे में लाया जाए। ए टी एम ए ने बतलाया है कि निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है और जहां तक इस जांच का संबंध है ए टी एम ए को एक हिबद्ध पक्ष के रूप में ही माना जाना चाहिए।

(ख) ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:-

- (i) उन्होंने कहा है कि वे पोलैंड और यूरोपीय संघ से एच एस आर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का जोरदार विरोध करते हैं क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त पाटन नहीं किया गया है। संबद्ध वस्तुओं की पूर्ववर्ती सबसे बड़ी घरेलू उत्पादक कंपनी मै. सिंथेटिक और कैमिकल्स लिमिटेड जुलाई, 1999 से बंद हो चुकी है। इसलिए जो कुछ भी आयात किए गए हैं वे केवल मांग आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए किए गए हैं क्योंकि मांग घरेलू आपूर्ति से अधिक है। इस प्रकार आयात केवल आपूर्ति में कमी की मात्रा तक किए गए हैं।

(ग) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैनुफैक्चरर्स ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- (i) प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर करने का उद्देश्य एच एस आर की कीमतों को किसी न किसी बहाने से बढ़ाना है। पोलैंड या यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त पाटन नहीं हुआ है। मै. सिंथेटिक एंड कैमिकल्स लिमि., जिसने 85% एस बी आर उत्पादन करने का दावा किया है, बंद हो चुकी है और जो कुछ भी आयात हो रहे हैं वे केवल मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए हो रहे हैं क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक है।

(घ) अन्य

- (i) मै. ऋषिरूप पॉलीमर्स प्रा. लिमि., मुम्बई ने सूचित किया है कि वे जांच अवधि के दौरान कथित देशों से उक्त वस्तुओं के न तो निर्यातक हैं न आयातक अपितु उसने एक हितबद्ध पक्ष होने का अनुरोध किया है क्योंकि सीगैट के खिलाफ दर्ज उनकी अपील में जांच के अधीन वस्तु से संबंधित एक इसी प्रकार का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। यह उत्पाद एस बी आर के संबंध में है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है। मै. एपार इंडस्ट्रीज लिमि., इस तर्क पर इस मामले का खंडन करने के लिए कहा है कि यह उत्पाद अध्याय 3903.9000 के अधीन आता है जो अध्याय 40 एस बी आर-1900 श्रृंखला के अधीन आने वाले उत्पाद के समान है। चूंकि इस कार्रवाई का उद्देश्य ऊपर उल्लिखित मामले की वर्तमान जांच के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्वीकृति की पुष्टि की अप्रत्यक्ष कोशिश करना है, इसलिए हमें इस पर कड़ी आपत्ति है। कोरिया से एस बी आर के आयात से संबंधी अंतिम जांच परिणाम में पूर्ववर्ती प्राधिकारी का मानना है कि उत्पाद के ओ एस वाई एन के एच एस 68 एक संश्लिष्ट रेजिन है जो अध्याय 3903.90 के अंतर्गत आती है और यह सिंथेटिक ब्यूटाडीन को पॉलीमर है जिसे उस समय चल रही जांच के दायरे में शामिल नहीं किया जाना था। डब्ल्यू टी ओ नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार हम केवल जांचाधीन वस्तु के बारे में स्पष्टीकरण के लिए तथा आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक हितबद्ध पक्ष के रूप में शामिल होना चाहते हैं ताकि इस चल रही जांच के किसी निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप एक अन्य पाटनरोधी जांच में हमारे एक लंबित मामले में कोई अप्रत्यक्ष अथवा घुमाफिराकर कोई हवाला न दिया जा सके।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोधों की जांच की गई है और उन पर इस जांच परिणाम में उचित जगह पर उस सीमा तक विचार व कार्रवाई की गई है, जहां तक वे नियमानुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं।

### 1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद हाई स्टाइटीन ब्यूटाडीन कार्पोलीमर है जिसे सभी ग्रेडों और रूपों का हाई स्टाइटीन रेसिन/रबड़ (एस एस आर) भी कहा जाता है। एच एस आर में हाई स्टाइटीन रेसिन लेटेक्स मास्टर बैच से संबंधित एस वी आर 1900 श्रृंखला और हाई स्टाइटीन री-इनफोरमेमेंट पालीमर वर्ग का एच एस वी आर शामिल है। एच एस आर का विनिर्माण केवल स्टाइटीन ब्यूटाडीन रबड़ (एस बी आर) के उत्पादकों द्वारा किया जाता है और इसकी खपत केवल रबड़ उद्योग में होती है। एच एस आर सीमा शुल्क उपशीर्ष सं. 4002.1902 के अंतर्गत वर्गीकृत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की निकासी शीर्ष 3903.9000 अर्थात् स्टाइटीन के अन्य पालीमर्स के अधीन भी किए जाने की सूचना है। एस बी आर 1500 और 1700 सीरीज को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इसलिए यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

### 2. समान वस्तु

प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए हाई स्टाइटीन ब्यूटाडीन कोपालीमर (एच एस आर) में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों के गुण समान हैं और ये तकनीकी व वाणिज्यिक रूप से ~~अन्य~~ प्रयोग उद्योग में अर्थात् रबड़ एवं फुटवेयर उद्योग में प्रतिस्थापनीय हैं।

इसलिए प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजन से यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु नियम 2 (घ) के अर्थ में समान वस्तुएं हैं।

### 3. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै. एपार इंडस्ट्रीज लिमि., और मै. एपकोटेक्स लैटिसेज लिमि., द्वारा दायर की गई है। प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक मात्र उत्पादक हैं। इसलिए नियम 5 (क) और (ख) तथा नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की शर्त को पूरा करते हैं।

### 4. सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

धारा 9(क) (1) (ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या

- (ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-
- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत:

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहाँ वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो, तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।

(क) यूरोपीय संघ का क्षेत्र

- (i) मै. बेयर इंटरनेशनल एस ए, स्विटजरलैंड
- (क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रस्तुत नहीं की हैं । उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान यू के में अपने ग्राहकों में से एक को बेची गई संबद्ध वस्तुओं अर्थात् क्राइलीन एच एस 260 ग्रेड की बिक्री का केवल एक बीजक प्रस्तुत किया है । इस बीजक के आधार पर संबद्ध वस्तु की औसत निवल बिक्री कीमत \*\*\* ई यू आर/मी.टन बैठती है । प्राधिकारी ने वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)द्वारा यथा अधिसूचित आयात दरों के आधार पर इस बिक्री कीमत को \*\*\* डालर/प्रति मी-टन के रूप में उल्लिखित किया है । तथापि, चूंकि उत्पादन लागत के कोई ब्यौरे नहीं मुहैया कराए गए हैं इसलिए यह मूल्यांकन करना संभव नहीं है कि यह व्यापार के सामान्य रूप में किया गया कारोबार है । प्राधिकारी यह भी उल्लेख करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान श्रीलंका को किए गए निर्यातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं लेकिन इनका भी संदर्भ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उत्पादन लागत तथा उत्पादन लागत के घरेलू बिक्रियों के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं जिससे कि इनका मूल्यांकन तीसरे देशों के पाटित या गैर पाटित निर्यातों के रूप में किया जा सके । इसलिए प्राधिकारी प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन से इस सूचना की अनदेखी करते हैं और अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन से याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को संदर्भित करने का प्रस्ताव करते हैं । इसलिए सामान्य मूल्य परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर उल्लिखित किया गया है । जो \*\*\* अमरीकी डालर/मी.टन बैठता है ।

(ख) कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं अर्थात् क्राईलीन एच एस 260 के किए गए निर्यात के निर्यात बीजक की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं। श्रीलंका का निर्यात बीजक दर्शाता है कि समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा के लिए क्रमशः \*\*\* एवं \*\*\* अमरीकी डालर प्रति मी.टन के हिसाब से लगाया गया है। प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा के इस स्तर को भारत और श्रीलंका की समीपता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के संबंध में निर्यातक ने कोई ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराया है, भारत की निर्यात बिक्री के लिए संदर्भित करने का प्रस्ताव किया है इसके अलावा समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा के समायोजनों के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय भाड़ा, एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पत्तन रखरखाव पर हुए व्यय के आधार पर क्रमशः \*\*\*,\*\*\* एवं \*\*\* अमरीकी डालर/प्रति मी.टन तक समायोजन की मंजूरी देने का भी प्रस्ताव किया है। संबद्ध वस्तुओं की जांच अवधि के दौरान भारत के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डालर/मी.टन बैठती है।

यूरोपीय संघ के क्षेत्र के अन्य निर्यातक/उत्पादक

सामान्य मूल्य

मैसर्स बेयर इंटरनेशनल एस ए की सूचना को उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अंगीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मैसर्स बेयर इंटरनेशनल एस ए द्वारा दी गई सूचना अपूर्ण है। चूंकि किसी भी अन्य निर्यातक/आयातक ने सूचना नहीं दी है इसलिए, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना को उपयुक्त समायोजनों के साथ अपनाने का प्रस्ताव किया है। जांच अवधि में परिकलित सामान्य मूल्य \*\*\* डालर/मीट्रिक टन बैठता है।

निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दी गई निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, कमीशन और पत्तन हैंडलिंग पर क्रमशः \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*\*, और \*\*\* डालर/मीट्रिक टन तक की सीमा तक समायोजनों के साथ अपनाने का प्रस्ताव किया है। जांच अवधि में कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मीट्रिक टन बैठती है।

ख) पोलैंड

i) मैसर्स फर्मा कैमिकजना डवोरी, एस ए

क) सामान्य मूल्य

निर्यातक/उत्पादक ने के ई आर 1904 ग्रेड की सिंथेटिक रबड़, अर्थात् जांच अवधि में पोलैंड के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के ग्रेडों में से एक ग्रेड, की उपभोक्ता-वार बिक्रियों के ब्यौरे दिए हैं। उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि में घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री संबंधी कीमत ढांचा और उत्पादन लागत भी उपलब्ध कराई है। निर्यातक/उत्पादक ने यह इंगित किया है कि उन्होंने घरेलू बिक्रियों पर अनन्य रूप से \*\*\* डालर/मीट्रिक टन के बिक्री संबंधी खर्च किए हैं। निर्यातक/उत्पादक ने भारत में अपने एजेंटों को दिए गए कमीशन के ब्यौरों के साथ-साथ संबद्ध वस्तु की निर्यात बिक्रियों के कतिपय बिक्री खर्चों का भी अपने आवेदनों में उल्लेख किया है। प्राधिकारी घरेलू बिक्रियों पर और कमीशन पर हुए खर्चों को सह-संबद्ध करने के पश्चात् नोट करते हैं कि समायोजनों की मात्रा, जिसके बारे में घरेलू बिक्रियों के लिए अनन्य रूप से दावा किया गया है, वास्तविक प्रतीत नहीं होती है और इसके अलावा यह कि इन समायोजनों के समर्थन कोई साक्ष्य/स्पष्टीकरण भी साथ में नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक द्वारा दिए गए उत्पादन लागत के ब्यौरों के आधार पर घरेलू बाजार में कुछ उपभोक्ताओं को की गई बिक्रियां उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत से कम हैं और इसलिए ये व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं आती है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II के अनुसार इन सौदों को शामिल किया है जो व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं थे। प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ भी प्राधिकारी घरेलू बिक्रियों के लिए अनन्य रूप से दावा किए गए बिक्री और प्रशासनिक खर्चों को उचित नहीं मानते हैं। जांच अवधि में सामान्य व्यापार प्रणाली में भारित औसत घरेलू बिक्री कीमतें \*\*\* डालर/मीट्रिक टन बैठती हैं। इस बिक्री कीमत का सामान्य कीमत के रूप में उल्लेख किया गया है और अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बिक्री खर्चों पर भी कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है।

ख) कारखानद्वार पर निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक ने भारत को संबद्ध वस्तु अर्थात् के ई आर 1904 ग्रेड सिंथेटिक रबड़ अर्थात् जांच अवधि में संबद्ध वस्तु के माह-वार निर्यात बिक्रियों के ब्यौरे दिए हैं। निर्यातक/उत्पादक ने भारत को किए गए निर्यातों के लिए बिक्री संबंधी कीमत ढांचे में अपने एजेंटों को छूट/कमीशन, पैकिंग, अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा पर क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, और \*\*\* डालर/मीट्रिक टन की सीमा तक के निर्यात कीमत संबंधी विभिन्न समायोजनों को इंगित किया है। निर्यातक ने जांच अवधि में \*\*\* डालर मी.टन की सीमा तक एक और वापसी का भी उल्लेख किया है। निर्यातक ने निर्यात बीजक और वैट की गणना भी उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन लागत में निर्यातक/उत्पादक ने \*\*\* डालर/मी.टन की सीमा तक की

निर्यात बिक्रियों के लिए बिक्री खर्चों पर हुई लागतों का भी उल्लेख किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ निर्यातक/उत्पादक द्वारा यथा-उल्लिखित समायोजनों पर विचार किया है। भारत को कारखाना द्वार पर भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मी.टन निकलती है।

### पोलैंड के अन्य निर्यातक/उत्पादक

#### सामान्य मूल्य

चूंकि किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने सूचना नहीं दी है इसलिए प्राधिकारी ने उपयुक्त समायोजनों के साथ उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य पर याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना को मानने का प्रस्ताव किया है। जांच अवधि में परिकलित सामान्य मूल्य \*\*\* डालर/मी.टन बैठता है।

#### निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन भाड़ा और कमीशन पर क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* डालर/मी.टन की सीमा तक के समायोजनों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा यथा-उपलब्ध निर्यात कीमत को लेने का प्रस्ताव रखा है। जांच अवधि में कारखानाद्वार पर निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मी.टन बैठती है।

### 5. पाटन- सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"डंपिंग का मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के इसी स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि की दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी; अंतर में शामिल हैं बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।"

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की कारखाना द्वार पर भारित औसत निर्यात कीमत के साथ तुलना की है।



संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं-

निर्यातक/उत्पाद	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर/मी. टन)	निर्यात कीमत (अमरीकी डालर/मी. टन)	पाटन मार्जिन(%)
<b>यूरोपीय संघ क्षेत्र</b>			
मै. बेयर इंटरनेशनल, एस ए स्विटजरलैंड	*****	*****	103.03
यूरोपीय संघ क्षेत्र के अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	128.7
<b>पोलैंड</b>			
मै. फर्मा कैमिकजना डवोरी एस ए	*****	*****	4.9
अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	115.9

उपरोक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक हैं ।

## 6. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के अंतर्गत जब क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में " ..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव, ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभावों समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए " घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा । मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्य में पर्याप्त गिरावट रही है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक स्थिर रखना है अथवा मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती ।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उपरोक्त नियमों के अनुबंध II (iv) के अनुसार उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभ प्रदत्ता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन जैसे संकेतकों पर विचार किया गया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं ।

प्राधिकारी का मत निम्नानुसार है:

i) जेनों उत्पादकों का समग्र क्षमता उपयोग वर्ष 1997-98 में 72.73 % से जांच अवधि में घटकर 57.13 % हो गया।

ii) हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 1997-98 और 1998-99 की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि यह वृद्धि पाटन आयातों के फलस्वरूप क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के नीचे रही, जिसकी वजह से कीमत कम किए जाने के कारण वित्तीय घाटा हुआ।

iii) उत्पाद की मांग में गिरावट नहीं आई और इसलिए इससे उद्योग को क्षति नहीं पहुंची है।

iv) उपरोक्त आर्थिक मापदण्ड सामूहिक और संचयी रूप से यह स्थापित करते हैं कि पाटन के कारण घरेलू को वास्तविक क्षति हुई है।

### भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

कुछेक हितबद्ध पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपयोक्ता उद्योग (विशेष रूप से लघु उद्योग) प्रभावित होगा क्योंकि यह खड़ उत्पाद के विनिर्माताओं के लिए एक अनिवार्य निविष्टि है। प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त तर्कों पर विचार किया गया और उनका मानना है कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो और भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा और घरेलू उद्योग के ह्रास को रोका जा सकेगा तथा संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होंगे। पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

**पहुंच मूल्य :** संबद्ध वस्तु के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य से भारत सी आई एफ कीमत में एक प्रतिशत उतराई प्रभार और प्रचलित स्तर पर सीमाशुल्क (धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) जोड़ने के बाद किया गया है।

## (घ) निष्कर्ष

पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह पाया गया है कि:

(क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी रुपों का भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया ।

(ख) घरेलू उद्योग को इसके बाजार हिस्से में गिरावट के कारण वार्षिक क्षति हुई है, और आयातित संबद्ध वस्तुओं की कम पहुंच कीमत के द्वारा कीमत ह्रास के फलस्वरूप निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) में कमी आने के कारण वित्तीय घाटा हुआ है ।

(ग) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी रुपों/ग्रेडों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि विचाराधीन<sup>मूल्य</sup> से कि पैरा ग(1) में इंगित किया गया है, को “स्टाइरीन के अन्य पोलिमर” की निकासी अन्य श्रेणी अर्थात् सीमाशुल्क शीर्ष 3903.9000 के अंतर्गत की जाती है तब इन उत्पादों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा ।

(घ) पाटन मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने पर विचार किया गया जिससे घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके । तदनुसार यह प्रस्ताव है कि अन्तिम निर्धारण होने तक सीमाशुल्क टैरिफ के सीमाशुल्क अध्याय 40 के उपशीर्ष संख्या 4002.1902 के अंतर्गत आने वाले यूरोपीय संघ और पोलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी रुपों एवं ग्रेडों के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे यथा निर्धारित अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

क्र०सं०	निर्यातक/उत्पादक	उत्पाद	शुल्क की राशि अमरीकी डालर/मी० टन
1.	<u>पोलैंड</u> मै० फर्मा कैमिकजना ड्वोरी एसए	उच्च स्टाइरीन रेजिन लैटेक्स मास्टर बैच/उच्च स्टाइरीन पुनः प्रत्यावर्तित पोलिमर से संदर्भित एस बी आर 1900 श्रृंखला के दायरे में उच्च स्टाइरीन रेजिन/रबड़ (एचएसआर)के, केईआर1904 सहित सभी ग्रेड	45.7

2.	सभी अन्य निर्यातक/उत्पादक  <b>यूरोपीय संघ क्षेत्र</b> मै0 बेयर इंटरनेशनल एसए	उच्च स्टाइरीन रेजिन लैटेक्स मास्टर बैच/उच्च स्टाइरीन पुनः प्रत्यावर्तित पोलिमर से संदर्भित एस बी आर 1900 श्रृंखला के दायरे में उच्च स्टाइरीन रेजिन/रबड़ (एचएसआर)के, केईआर1904 सहित सभी ग्रेड  उच्च स्टाइरीन रेजिन लैटेक्स मास्टर बैच/उच्च स्टाइरीन पुनः प्रत्यावर्तित पोलिमर से संदर्भित एस बी आर 1900 श्रृंखला के दायरे में उच्च स्टाइरीन रेजिन/रबड़ (एचएसआर)के, क्राइलिन एचएस 260 सहित सभी ग्रेड	845.5  799.25  886.3
----	---	--	----------------------------------

ड.) **आगे की प्रक्रिया:** प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकारी सभी इच्छुक पार्टियों से इन निष्कर्षों के बारे में टिपणियां आमंत्रित करते हैं और उन पर अंतिम निष्कर्ष निकालते समय विचार किया जाएगा ;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों/संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माताओं, आयातकों, याचिकाकर्ता और अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से संबोधित किया जा रहा है जो पत्र के प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है ,

(ग) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन करेंगे ;

(घ) प्राधिकारी मौखिक निवेदन के लिए सभी हितबद्ध पार्टियों को अवसर प्रदान करेंगे, जिसके लिए सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा ;

(ड.) अंतिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे ।

एल. बी. मन्ना, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2001

**PRELIMINARY FINDINGS**

**Sub. : Anti-Dumping investigation concerning imports of High Styrene Butadiene Copolymer/High Styrene Resin/Rubber (HSR) from originating in or exported from Poland and Territory of European Union.**

**No. 22/1/2000-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from the M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd. (hereinafter also referred to as petitioner) having registered offices at Apar House, Corporate Park, Sion-Trombay Road, Chambur, Mumbai-400021 and 49-53, Mahavir Centre, Plot No. 77, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400073 respectively on behalf of domestic industry, alleging dumping of High Styrene Butadiene Copolymer/High Styrene Resin/Rubber (HSR) (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Poland and Territory of European Union(hereinafter referred to as subject countries).

- ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.
- iii) The Authority on the basis of sufficient prima-facie evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Poland and Territory of European Union. The Authority notified the Embassy of Poland and Delegation to the European Commission in New Delhi (hereinafter also called Embassies of the subject countries) about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rule.
- iv) The Authority issued a public notice dated 20.12.2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under custom Code 4002.1902 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Poland and Territory of European Union.
- v) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2):
- vi) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter.
- vii) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
- viii) The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the petition was also provided to other interested parties, wherever requested.

- ix) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers in the subject countries in accordance with the Rule 6(4):
1. M/s Bayer AG, Germany
  2. M/s Enichem Elastomeri S.r.l., Italy
  3. M/s Huls AG, Germany
  4. M/s Bunawerke Huls Gmbh, Germany
  5. M/s Chemical Company "Dwory" SA, Poland
- x) The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy of the subject countries alongwith a list of known exporters/producers.
- xi) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):
1. M/s Banik Rubber, Calcutta
  2. M/s B Rubber, Ghaziabad
  3. M/s Oswal Industries, Delhi
  4. M/s Lakhani, Haryana
  5. M/s Aarthi Enterprise, Noida
- xii) Response/ information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/producers of the subject countries:
1. M/s Firma Chemiczna Dwory S.A. , Poland filed by M/s Arthur Anderson
  2. M/s Bayer International S.A., Switzerland
- xii) Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following Importers/user Associations/other interested parties:

1. M/s M/s Paragon Rubber Industries, Kerala}filed by
2. M/s Leo Rubbers, Kerala }Strategic Law
3. M/s Paragon Polymers, Kerala }Group
4. M/s Malaya Trade Impex P Ltd, Kottayam (filed by M/s  
Sharma Associates)
5. M/s All India Federation of Rubber Footwear  
Manufacturers, New Delhi
6. Automotive Tyre Manufacturers Association, New Delhi
7. All India Rubber Industries Association, Mumbai

M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai have filed response in capacity of an interested party other than importer/exporter.

- xiv) Additional information regarding various injury parameters, including cost of production was also sought from the petitioner, which was also furnished.
- xv) The Authority verified the information provided by the petitioner to the extent considered necessary.
- xvi) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- xvii) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India was worked out on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and by analysing the cost information furnished by the petitioner.
- xviii) \*\*\*\*in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xix) Investigation was carried out for the period starting from 1.1.2000 to 30.9.2000 i.e. the period of investigation (POI).



## **B . VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

### **1. PETITIONER'S VIEWS**

#### **a) ON PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

i) The complete description of the product is high Styrene Butadiene Copolymer also called high Styrene Resin/Rubber (HSR) which covers SBR 1900 series and HSRB. SBR 1900 series refers to high Styrene resin master batch (also called emulsion resin rubber master batch). HSRB refers to high Styrene reinforcement polymers.

ii) HSR can be of various grades and forms and is produced in granular and bale form. The grade of HSR is normally described in terms of Styrene content and mooney viscosity. Indian industries produce HSR which is equivalent of all those grades which are being imported at present from Poland and European Union. Further the industry is also in a position to produce equivalent of all those grades which are being produced in Poland and European Union even though the same are not being exported to India at present.

iii) HSR is manufactured by producers of Styrene butadiene rubber only and is consumed in the rubber industry.

iv) HSR has been categorized under custom sub heading 4002.1902 in chapter 40 and is also imported under custom sub-heading 3903.9000. The only difference between the goods imported under chapter 39 and 40 is that of percentage content of styrene which does not render the product as different and the product will have almost similar technical and commercial applications.

v) HSR usage requires fine tuning of the production process to accommodate the usage of HSR made by different suppliers. Consumers in India as other parts of the world can use HSR produced by any manufacturer interchangeably without making any change in the plant and equipment.

vi) There is no direct substitute for HSR. There are other polymers such as EVA etc. used in footwear application. However, EVA does not directly substitute HSR.

vii) There is no significant difference in the HSR produced by the petitioner and the HSR exported from the subject countries. There cannot be any difference in the technology adopted by M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd. and the technology adopted by the producers in Poland and European Union as HSR world over is produced by polymerisation technology. However, every producer fine tunes its production process considering available facilities and necessities.

#### b) ON DUMPING

i) The domestic industry has constructed the normal value for the exporters in the subject countries on the basis of the cost of production considering international prices of the major raw materials.

ii) The domestic industry has provided the export price on the basis of the secondary source during the POI with adjustments on ocean freight, marine insurance, commission, inland transport and port handling and port charges.

iii) The dumping margin for European Union has been stated at 140% while for the exporters from Poland at 126%.

#### C) ON INJURY AND CAUSAL LINK

The domestic industry has stated that the injury is evident from many parameters:-

i) Significant rise in dumped imports from subject countries in a very short period which indicates the likelihood of substantially increased importation in future.

ii) Substantial capacity available to export with the exporters in the subject countries given that other countries (who were hitherto exporting the material) have recently been effectively covered under anti-dumping duties from these countries.

- iii) Sufficient freely disposable capacities exists given that the consumption world wide is far less than the capacities built up and the exporters in these countries have very quickly attempted to capture the market upon imposition of duties on other countries.
- iv) Imports are entering India at prices which have and will continue to have a significant depressing effect on domestic prices.
- v) Imports are entering at prices which are significantly below the price at which goods are being sold by the Indian producers. The imports are thus resulting in severe price undercutting and would resulting insignificant increase in imports or decline in the domestic price.
- vi) Losses of the domestic industry have piled up. The industry has been forced to sell at prices below the optimum cost of production and reasonable return on investments.
- vii) Operating margins of the domestic industry have been declining substantially as a result of severe price undercutting.
- viii) Stock with the domestic industry have piled up.
- ix) Capacity utilization of the industry has remained sub optimal. The industry has not been able to utilize its plant optimally in spite of imposition of anti-dumping duties on other countries.
- x) Domestic industry market share has been reducing in view of the dumped imports and the market share of these countries is increasing.
- xi) Employees with the domestic industry are completely demoralized and are leaving the industry as a result of continued dumping of the product in the market.
- xii) It has become un-remunerative to continue the operations under these circumstances.

- xiii) The domestic industry is unable to grow in view of no investments forthcoming from stakeholders and internal accruals etc. as a result of continued dumping of this product in the Indian market..
- xiv) One manufacturer (Synthetic & Chemicals Ltd.) has already applied to BIFR.

## 2. EXPORTER'S VIEWS

a) M/s Firma Chemiczna Dwory S.A. Poland has made the following submissions:-

- i) The exporter has provided details of the domestic selling price, export price and various adjustments thereof during the POI for the subject goods in the questionnaire as prescribed.
- ii) The exporter has sought adjustments on the export sales on account of discounts/commissions paid to their agent in India, inland freight, overseas freight, packing and VAT refund. The exporter has also provided the cost of production of the subject goods during the POI.
- iii) The exporter has submitted that as per their data there is no dumping margin for the exports made to India.

b) M/s Bayer International S.A., Switzerland has made the following submissions:-

- i) The exporter has indicated that they have already been subjected to anti-dumping investigation on SBR and were exonerated and are surprised that once again a similar investigation has been initiated on one specific grade of SBR.
- ii) The exporter has provided a copy of the one invoice on domestic sales, one invoice on exports to Sri Lanka and a few invoices on exports to India during the POI.
- iii) The exporter has indicated that they have exported 437 tonnes of Krylene HS 260 grade to India and that it contributes only 2% of the total consumption for the year 2000. The exporter has

submitted that this volume is not significant to cause injury to the indigenous producers.

### 3. IMPORTERS AND USER ASSOCIATIONS VIEWS

a) M/s Paragon Rubber Industries, M/s Leo Rubbers and M/s Paragon Polymers has made the following submissions:-

i) Details on imports made by them from Japan and USA of the subject goods in the POI have been provided and it has been indicated that imports from Poland were made recently only.

ii) It has been indicated that they manufacture rubber Hawai slippers which is the most common footwear used by lower middle class and rural people because of the low price and that HSR is the main ingredient to manufacture good quality Hawai chappal. Any increase in the cost of synthetic rubber will affect their cost of production and that the domestic producers products are very inferior in quality and that their production capacity is also less whereas the current demand for HSR for Indian footwear industry is still above 30,000 MT per year.

iii) The importers have provided details on imports made by them from Japan and USA of the subject goods in the POI and have indicated that they are importing from Japan at a higher cost by paying anti-dumping duty. They have indicated that the quality of domestic manufacturer is inferior and cannot meet their requirement both supply wise and quality wise. They have also now started importing from Poland.

iv) The levy of anti-dumping duty will adversely affect the small scale sector industries and thereby increase the burden of common man in India.

b) M/s Malaya Trade Impex P Ltd. has made the following submissions:-

i) They have provided details of imports of subject goods viz. KER HSR 1904 grade from Poland in the POI alongwith supportive invoices. The importer has also provided details on imports from other countries also.

a) M/s Automotive Tyre Manufacturers Association has made the following submissions:-

i) HSR is not used by tyre industry and that their apprehension is that the two grades viz. SBR 1702 and 1502 which are consumed by the tyre industry may also be brought under the purview of the investigation. ATMA has indicated that the Directorate may ensure that this does not happen and that ATMA be treated as an interested party as far as this investigation is concerned.

b) All India Rubber Industries Association has made the following submissions:-

i) They have stated that they strongly protest levy of anti-dumping duty on HSR from Poland and European Union as there is no substantial dumping of the subject goods. The erstwhile largest domestic producer of the subject goods M/s Synthetic and Chemicals Ltd. has closed down since July 1999. Hence whatever imports are taking place they are just to bridge the demand supply gap as the demand exceeds the domestic supply. As such the imports are only to the extent of short fall in supply.

c) All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers has made the following submissions:-

i) The purpose of filing the petition before the authority is to increase prices of HSR on one pretext or the other. There is no substantial dumping of subject goods from Poland and European Union. M/s Synthetic and Chemicals Ltd. who claimed to produce 85% of SBR

is closed down and whatever imports are taking place these are just to bridge the gap between the demand and supply as the demand exceeds the supply.

**d) Others:**

i) M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai have indicated that they are neither the concerned exporters or importers of the said articles under investigation from the named countries but desired to be an interested parties because a similar dispute is pending concerning the article under investigation before the Supreme Court in our Appeal filed against CEGAT. It is with regard to the product SBR to which the anti-dumping duty has to be made applicable. M/s Apar Industries Ltd. have said to confuse the affairs with the argument that the product falls under Chapter 3903.9000 which is same as that under Chapter 40 SBR-1900 series. Since this action tends to indirectly seek the confirmation of the approval of the DA via the current investigation of the issue mentioned above we strongly object the same. In the final findings concerning imports of SBR from Korea, the previous authority has held that the product KOSYN-KHS-68 is a synthetic Resin falling under chapter 3903.90 and it is synthetic butadiene co polymer which was not to be covered by the scope of investigation undertaking at that time. We desire to participate as interested party as provided in the WTO rules solely to clarify and to dispute the article under investigation so that no indirect or circumvented references are inferenced to our pending matter in the other anti-dumping investigation as a fall out from any findings in this current investigation.

**C. EXAMINATION BY AUTHORITY**

The foregoing submissions made by the exporters, the importers, the petitioner and other interested parties have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case.

## 1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present investigation is High Styrene Butadiene Copolymer, also called High Styrene Resin/Rubber (HSR) of all grades and forms. HSR covers SBR 1900 series referring to High Styrene Resin Latex Master batch and HSBR referring to High Styrene re-informement Polymer. HSR is manufactured by producers of Styrene Butadiene Rubber (SBR) only and is consumed in rubber industry. HSR is classified under customs subheading NO. 4002.1902. The authority notes that the product under consideration has also been reported to be cleared under head 3903.9000 viz. other Polymers of Styrene. The SBR 1500 and 1700 series are not covered in the scope of investigation. The classification, is therefore, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

## 2. LIKE ARTICLE

The authority notes that there is no significant difference in the goods produced by the Indian industry and High styrene Butadiene Copolymer (HSR) exported from the subject countries. Both are claimed to have similar characteristics and are technically and commercially substitutable in the end use industry viz. the rubber and footwear industry.

The Authority, therefore, for the purpose of the Preliminary Findings holds that the subject goods imported from the subject countries and that manufactured by the domestic industry are Like Article within the meaning of the Rule 2(d).

## 3. DOMESTIC INDUSTRY

The petition has been filed M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd. The authority holds that the petitioners are the only producers of Subject goods in India and, therefore, satisfies the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(a) and (b) and Rule 2(b).



#### 4. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

Under Section 9A(1)(c), normal value\* in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub section (6); or

(b) the cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

## A. Territory of European Union

### i) M/s Bayer International S.A., Switzerland

#### a) Normal value

The authority notes that the exporter/producer has not provided the information as per the prescribed questionnaire. The producer/exporter has only provided one sales invoice of the subject goods viz. Krylene HS 260 grade sold to one of their customers in UK during the POI. The average net selling price of the subject goods on the basis of this invoice comes to \*\*\* EUR/MT. The authority has on the basis of the import rates as notified by Ministry of Finance (MOF) referenced this selling price as \*\*\*\$/MT. However, since no Cost of production details have been provided it is not possible to evaluate as to this transaction is in the normal course of trade. The authority also notices that exporter/producer has provided the details of exports made to Sri Lanka during the period of investigation which also cannot be referenced as no data for cost of production and domestic sales is available to evaluate third country exports as dumped or non-dumped. The authority, therefore, disregards information for the purpose of preliminary determination and proposes to reference the information as provided by the petitioner for the purpose of preliminary determination pending final determination. The normal value has, therefore, been referenced on the basis of the constructed cost of production which comes to \*\*\*\$/MT.

#### b) Ex factory Export price

The authority notes that the exporter/producer has provided copies of export invoices of the subject goods viz. Krylene HS 260 to India in the POI. The export invoice to Sri Lanka indicates incidence of ocean freight and ocean insurance to an extent of \*\*\* & \*\*\*\$/MT respectively. The authority proposes to reference these levels of

ocean freight and ocean insurance on export sales to India keeping in view the proximity of Sri Lanka to India and the fact that no details have been provided by the exporter regarding the exfactory export price to India. Further to adjustments on ocean freight and ocean insurance, the authority also proposes to grant adjustments on account of expenses incurred on inland freight, commission paid to agent and port handling to an extent of \*\*\*, \*\*\* & \*\*\*\$/MT respectively on the basis of the information provided by the petitioner. The exfactory export price of the subject goods in the POI to India comes to \*\*\*\$/MT.

### Other exporters/producers of Territory of European Union

#### Normal value

The information of M/s Bayer International S.A. cannot be adopted for the producers/exporters as the information by M/s Bayer International S.A. is not complete. As no other exporter/producer has provided information, the authority proposes to adopt the information as provided by the petitioner on the normal value constructed on the basis of the cost of production with appropriate adjustments. The constructed normal value in the POI comes to \*\*\*\$/MT.

#### Export price

The authority proposes to adopt the export price as provided by the petitioner with adjustments on ocean freight, insurance, inland freight, commission and port handling to an extent to \*\*\*, \*\*\*,\*\*\*, \*\*\* & \*\*\*\$/MT respectively. The ex-factory export price in the POI comes to \*\*\*\$/MT.

### B. POLAND

#### i) M/s Firma Chemiczna Dwory S.A.

##### a) Normal value

The exporter/producer has provided details of the customer-wise sales of KER 1904 grade synthetic rubber viz. one of the grades of the subject goods in the home market in Poland in the POI. The producer/exporter has also provided the sales price structure and the cost of production for the domestic sales in the POI. The exporter/producer has indicated that they have incurred \*\*\*\$/MT on selling expenses exclusively on the domestic sales. The exporter/producer has also in their submission indicated certain selling expenses of the export sales of the subject goods to India alongwith the details on the commission paid to their agent in India. The authority after co-relating the expenses incurred on domestic sales and that on the commission notes that the quantum of adjustments exclusively claimed for domestic sales does not appear to be realistic and further that it is also not supported by any evidence/explanation. The authority further notes that on the basis of the cost of production details provided by the exporter/producer sales to certain customers in the domestic market are below the cost of production as claimed by the producer/exporter and are, therefore, not in the normal course of trade. The authority as per Annexure II of the Anti-Dumping Rules has excluded these transactions which are not in the normal course of trade. Also for the purpose of Preliminary Findings, the authority does not consider it appropriate to grant the adjustment of selling and administrative expenses exclusively claimed for the domestic sales. The weighted average domestic selling prices in the normal course of trade comes to \*\*\*\$/MT in the POI. This selling price is referenced as the normal value also as no adjustment is granted on selling expenses for the purpose of preliminary determination pending final determination.

b) Ex-factory Export price

The authority notes that the exporter/producer has provided month-wise export sales to India of the subject goods viz. KER 1904 grade synthetic rubber viz. the subject goods in the POI. The exporter/producer has indicated in the sales price structure for exports to India, the various adjustments on the export price viz. discounts/commission to their agent, packing, inland freight, overseas freight to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* & \*\*\* \$/MT respectively. The

exporter has also indicated a VAT refund to an extent of \*\*\*\$/MT in the POI. The exporter has provided the exports invoice and calculation of VAT. The authority notes that in the cost of production the exporter/producer has also indicated costs incurred on the selling expenses for the export sales to an extent of \*\*\*\$/MT also. The authority for the purpose of preliminary findings considers the adjustments as indicated by the exporter/producer. The weighted average ex-factory export price for the subject goods to India comes to \*\*\*\$/MT.

#### Other exporters/producers of Poland

#### Normal value

As no other exporter/producer has provided information, the authority proposes to adopt the information provided by the petitioner on the normal value constructed on the basis of the cost of production with appropriate adjustments. The constructed normal value for the subject goods in the POI comes to \*\*\*\$/MT.

#### Export price

The authority proposes to adopt the export price as provided by the petitioner with adjustments on ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent to \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*& \*\*\*\$/MT respectively. The ex-factory export price in the POI comes to \*\*\*\$/MT.

### **5. DUMPING-Comparison of Normal Value & Export Price**

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in

conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price for evaluation of dumping margin.

The dumping margins for the producers/exporters of the subject goods in the subject countries are as under:--

Exporter/producers	Normal value (\$/MT)	Export price (\$/MT)	Dumping margin(%)
<u><b>Territory of European Union</b></u>			
M/s Bayer International S.A., Switzerland	*****	*****	103.03
All other exporters/ producers of Territory of European Union	*****	*****	128.7
<u><b>Poland</b></u>			
M/s Firma Chemiczna Dwory S.A.	*****	*****	4.9
All other exporters/producers	*****	*****	115.9

The above dumping margins are above the de minimis limits.

## 6. INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of

the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

**The Authority observes the following**

- i) The overall capacity utilization of the two producers has declined from 72.73% in 97-98 to 57.13% in the POI.
- ii) The selling price of the domestic industry has though increased in POI as compared to 98-99 and 97-98, the same has been, however, below the non-injurious price (NIP) on account of dumped imports leading to financial losses on account of price undercutting.
- iii) The demand of the product has not decreased and has, therefore, not contributed to the injury to the industry.
- iv) The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

**7. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

It has been argued by certain interested parties that the levy of anti-dumping duties, will affect the user industry (SSI in particular) as it is an essential input for manufacture of rubber products. The authority has considered the above argument and holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate dumping,

which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The authority recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products which manufactured with the usage of the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products are, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

#### **LANDED VALUE**

The landed value has been determined for the subject goods after adding on weighted CIF, the applicable level of custom duties (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges for the purposes of preliminary determination pending final investigation.

#### **D. CONCLUSIONS:**

It is seen, after considering the foregoing, that:

- a) The subject goods in all forms originating in or exported from the subject countries have been exported to India below its normal value.
- b) The domestic industry has suffered material injury by way of decline in its market share and financial losses due to depressed Net Sales Realization (NSR) on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods.
- c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries. The authority recommends anti-dumping duty on imports of all forms/grades of the subject goods falling under



Chapter 40 originating in or exported from the subject countries. It is also clarified that if the product under consideration as indicated in Para C(1) is cleared under the residual category of "other polymers of styrene" viz. Custom Head 3903.9000 then these goods would also be subjected to the anti-dumping duty.

- d) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that provisional anti dumping duties as set out below be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of all forms and grades of subject goods originating in or exported from European Union and Poland falling under Chapter 40 of the Customs sub-heading 4002.1902 of the Customs Tariff, pending final determination.

Sl.No.	1 Exporter/producer	2 Product	3 Amount of duty (\$/MT)
1.	<b><u>Poland</u></b>		
	M/s Firma Chemiczna Dwory SA	All grades including KER 1904 of High Styrene Resin/Rubber (HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch/High Styrene re-inforcement Polymer	45.7
	All other exporters/ producers	All grades including KER 1904 of High Styrene Resin/Rubber (HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch/High Styrene re-inforcement Polymer	845.5
2.	<b><u>Territory of European Union</u></b>		
	M/s Bayer International SA, Switzerland	All grades including Krylene HS 260 of High Styrene Resin/Rubber (HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch /High Styrene re-inforcement Polymer	799.25
	All other exporters/ producers	All grades including Krylene HS 260 of High Styrene Resin/Rubber (HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch /High Styrene re-inforcement Polymer	886.3

## **E. FURTHER PROCEDURE**

The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- b. Exporters/manufacturers of subject goods in subject countries, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- c. The Authority would conduct verifications to the extent deemed necessary;
- d. The Authority would provide opportunity to all interested parties for oral submissions, for which the date and time shall be communicated to all known interested parties separately;
- e. The Authority would disclose essential facts before announcing the final findings.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority